

EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

22 - 28 MARCH 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: Who was appointed as the Interim Part-Time Chairman of HDFC Bank after Atanu Chakraborty's resignation?

प्रश्न: अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद HDFC Bank का अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया?

- A) Sashidhar Jagdishan / सशिधर जगदीशन
- B) Atanu Chakraborty / अतनु चक्रवर्ती
- C) Keki Mistry / केकी मिस्त्री
- D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- E) Uday Kotak / उदय कोटक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Atanu Chakraborty, part-time chairman of HDFC Bank, resigned with immediate effect citing concerns related to “values and ethics.”
- HDFC Bank के अंशकालिक चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने “मूल्यों और नैतिकता” से जुड़े कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।
- Following the resignation, board members approached the Reserve Bank of India (RBI) for approval to appoint Keki Mistry as interim part-time chairman, which was quickly approved.
- इस्तीफे के बाद बोर्ड सदस्यों ने RBI से केकी मिस्त्री को अंतरिम अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी मांगी, जिसे तुरंत स्वीकृति मिल गई।
- RBI clarified that there were no governance or conduct issues at HDFC Bank.
- RBI ने स्पष्ट किया कि HDFC Bank में कोई प्रशासनिक या आचरण संबंधी समस्या नहीं है।
- The bank's stock fell by 5.1%, and its market capitalization declined significantly after the news.
- इस खबर के बाद बैंक का शेयर 5.1% गिरा और बाजार पूंजीकरण में बड़ी गिरावट आई।
- The board is also expected to approve the reappointment of MD & CEO Sashidhar Jagdishan.
- बोर्ड द्वारा MD & CEO सशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी मिलने की

संभावना है।

Ques: Which bank received a USD 500 million loan from an IFSC Banking Unit in GIFT City, Gujarat?

प्रश्न: GIFT सिटी, गुजरात में IFSC बैंकिंग यूनिट से 500 मिलियन USD का ऋण किस बैंक को मिला?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda received a USD 500 million loan from an IFSC Banking Unit located in GIFT City.
- बैंक ऑफ बड़ौदा को GIFT सिटी, गुजरात स्थित IFSC बैंकिंग यूनिट से 500 मिलियन USD का ऋण प्राप्त हुआ।
- The loan has a tenure of five years and will be used for general banking operations and corporate purposes.
- इस ऋण की अवधि पांच वर्ष है और इसका उपयोग सामान्य बैंकिंग कार्यों एवं कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- The deal saw participation from 13 investors across Asian markets, including Taiwan, South Korea, Japan, and Singapore.
- इस सौदे में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर सहित एशियाई बाजारों के 13 निवेशकों ने भाग लिया।
- MUFG Bank and HSBC acted as mandated lead arrangers for the loan.
- MUFG बैंक और HSBC ने इस ऋण के लिए अनिवार्य लीड अरेंजर की भूमिका निभाई।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
 - HQ : Vadodara, Gujarat
 - Tagline : India's International Bank
 - MD & CEO : Debadatta Chand
-

Ques: Jose Joseph Kattur, recently appointed as part-time chairman, is associated with which bank?

प्रश्न: हाल ही में पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त जोसे जोसेफ कट्टूर किस बैंक से जुड़े हैं?

- A) Federal Bank / फेडरल बैंक
- B) South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Jose Joseph Kattur has been appointed as non-executive part-time chairman of South Indian Bank.
- Jose Joseph Kattur को South Indian Bank का नॉन-एग्जीक्यूटिव पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
- The appointment is for a 3-year term effective from 23 March 2026, after approval from Reserve Bank of India.
- यह नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के बाद 23 मार्च 2026 से 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
- He succeeds VJ Kurian.
- वे VJ Kurian का स्थान लेंगे।

- He has over 30 years of experience at RBI (1991–2023) and has been an independent director since July 2024.
 - उनके पास RBI में 30+ वर्षों (1991–2023) का अनुभव है और वे जुलाई 2024 से स्वतंत्र निदेशक रहे हैं।
 - South Indian Bank was founded in 1929 and is headquartered in Thrissur.
 - South Indian Bank की स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय त्रिशूर में स्थित है।
-

Ques: According to the statement by Pankaj Chaudhary, what is the total amount of loans written off by banks in the last 11 financial years?

प्रश्न: पंकज चौधरी के अनुसार, पिछले 11 वित्तीय वर्षों में बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण राइट-ऑफ किए गए हैं?

- A) ₹5.50 लाख करोड़ / ₹5.50 लाख करोड़
- B) ₹7.25 लाख करोड़ / ₹7.25 लाख करोड़
- C) ₹9.75 लाख करोड़ / ₹9.75 लाख करोड़
- D) ₹12.00 लाख करोड़ / ₹12.00 लाख करोड़
- E) ₹15.00 लाख करोड़ / ₹15.00 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Banks have written off loans worth ₹9.75 lakh crore in the last 11 financial years.
- पिछले 11 वित्तीय वर्षों में बैंकों ने ₹9.75 लाख करोड़ के ऋण राइट-ऑफ किए हैं।
- The highest write-off was recorded in FY20 at ₹1.59 lakh crore.
- सबसे अधिक राइट-ऑफ FY20 में ₹1.59 लाख करोड़ रहा।
- Since then, the amount has been declining, reaching ₹47,568 crore in FY25.
- इसके बाद यह राशि घटती गई और FY25 में ₹47,568 करोड़ रह गई।
- Earlier trends show a steady increase: ₹31,723 crore (FY15), ₹40,416 crore

(FY16), ₹68,308 crore (FY17), and ₹99,132 crore (FY18).

- पहले के वर्षों में यह लगातार बढ़ा: ₹31,723 करोड़ (FY15), ₹40,416 करोड़ (FY16), ₹68,308 करोड़ (FY17) और ₹99,132 करोड़ (FY18)।
- In FY19, loan write-offs crossed ₹1 lakh crore, reaching around ₹1.59 lakh crore.
- FY19 में ऋण राइट-ऑफ ₹1 लाख करोड़ से अधिक होकर लगभग ₹1.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) imposed a ₹31.8 lakh penalty on which bank for non-compliance with rules related to inoperative accounts?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निष्क्रिय खातों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर ₹31.8 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया?

- A) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) HSBC / एचएसबीसी
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Standard Chartered / स्टैंडर्ड चार्टर्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The RBI imposed a ₹31.8 lakh penalty on HSBC.
- RBI ने ₹31.8 लाख का जुर्माना HSBC पर लगाया।
- The penalty was for non-compliance with RBI guidelines on inoperative accounts and unclaimed deposits.
- यह जुर्माना निष्क्रिय खातों और अनक्लेम्ड जमा से जुड़े RBI नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया।
- The action followed a statutory inspection based on the bank's financial

position as of 31 March 2025.

- यह कार्रवाई 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद की गई।
- HSBC was founded in 1865 and is headquartered in London, United Kingdom.
- HSBC की स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
- Its CEO (2026) is Georges Elhedery and Chairman is Brendon Nelson.
- इसके CEO (2026) Georges Elhedery हैं और चेयरमैन Brendon Nelson हैं।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) revised its approval for which bank's transition to a universal bank without requiring a Non-Operating Holding Company (NOHC) for now?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बदलने की मंजूरी में संशोधन करते हुए फिलहाल नॉन-ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी (NOHC) बनाने की आवश्यकता से छूट दी है?

- A) Ujjivan Small Finance Bank / उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- B) Equitas Small Finance Bank / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
- C) ESAF Small Finance Bank / ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) Jana Small Finance Bank / जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
- E) AU Small Finance Bank / एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The RBI has revised its earlier approval for AU Small Finance Bank to transition into a universal bank.
- RBI ने AU Small Finance Bank को यूनिवर्सल बैंक में बदलने की अपनी पूर्व मंजूरी में संशोधन किया है।
- It has allowed promoter shareholding to continue without setting up a Non-

Operating Holding Company (NOHC) for now.

- इसमें प्रमोटर शेयरहोल्डिंग को फिलहाल बिना नॉन-ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी (NOHC) बनाए जारी रखने की अनुमति दी गई है।
- The central bank clarified that an NOHC will be required only if the group sets up additional financial services entities in the future.
- केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि NOHC की आवश्यकता केवल तभी होगी जब समूह भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय सेवा संस्थाएँ स्थापित करेगा।
- Earlier, the RBI had granted in-principle approval on August 7, 2025, for the bank's transition from a small finance bank to a universal bank, valid for 18 months.
- इससे पहले RBI ने 7 अगस्त 2025 को स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जो 18 महीनों के लिए वैध थी।

About AU Small Finance Bank:

- Established : 2017
- HQ : Jaipur, Rajasthan
- CEO & MD : Sanjay Agarwal
- Tagline : Badlaav Humse Hai

Ques: RBI's "Utkarsh 3.0" framework will guide policy priorities for which period?

प्रश्न: RBI का "उत्कर्ष 3.0" फ्रेमवर्क किस अवधि के लिए नीति प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करेगा?

- A) 2025–2028
- B) 2026–2029
- C) 2024–2027
- D) 2027–2030
- E) 2023–2026

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India approved the budget for FY 2026–27.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट मंजूर किया।
 - It also approved the Medium-Term Strategy Framework “Utkarsh 3.0” for 2026–2029.
 - साथ ही “उत्कर्ष 3.0” मध्यम अवधि रणनीति फ्रेमवर्क (2026–2029) को मंजूरी दी गई।
 - The decision was taken at the 622nd Central Board meeting held in Patna.
 - यह निर्णय पटना में आयोजित 622वीं बैठक में लिया गया।
 - The meeting was chaired by RBI Governor Sanjay Malhotra.
 - बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर Sanjay Malhotra ने की।
 - The Board reviewed global and domestic economic conditions, geopolitical developments, and financial markets.
 - बोर्ड ने वैश्विक व घरेलू आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक घटनाओं और वित्तीय बाजारों की समीक्षा की।
 - “Utkarsh 3.0” focuses on strengthening regulation, financial stability, and institutional efficiency.
 - “उत्कर्ष 3.0” का उद्देश्य नियामक तंत्र को मजबूत करना, वित्तीय स्थिरता बढ़ाना और संस्थागत दक्षता में सुधार करना है।
 - RBI reported that states raised ₹45,960 crore via State Government Securities (SGS).
 - RBI के अनुसार राज्यों ने स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (SGS) के माध्यम से ₹45,960 करोड़ जुटाए।
 - Karnataka was the largest borrower, followed by Tamil Nadu and Madhya Pradesh.
 - कर्नाटक सबसे बड़ा उधारकर्ता रहा, इसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश रहे।
 - Other participants included Uttar Pradesh, West Bengal, and Haryana.
 - अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा शामिल रहे।
 - SGS auctions saw tenors up to 23 years, indicating strong long-term investor interest.
 - SGS नीलामी में 23 वर्षों तक की अवधि देखी गई, जो दीर्घकालिक निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है।
-

Ques: By 2030, India's digital economy is projected to contribute approximately what percentage to the country's GDP?

प्रश्न: 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देने का अनुमान है?

- A) 10%
- B) 13%
- C) 18%
- D) 20%
- E) 30%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India's digital economy is projected to contribute nearly 20% to the country's GDP by 2030, up from about 13% currently.
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक देश के GDP में लगभग 20% योगदान देने का अनुमान है, जो वर्तमान में लगभग 13% है।
- This growth is driven by digital sectors expanding at a much faster pace than the overall economy.
- यह वृद्धि डिजिटल क्षेत्रों की समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेज गति से वृद्धि के कारण हो रही है।
- India has signed agreements with more than 53 countries to export its Digital Public Infrastructure (DPI) model.
- भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को निर्यात करने के लिए 53 से अधिक देशों के साथ समझौते किए हैं।
- The DPI model includes systems for digital identity, payments, and data exchange.
- DPI मॉडल में डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय से संबंधित प्रणालियाँ शामिल हैं।
- India's software services exports, currently valued at around \$250 billion, are expected to shift towards higher-value, AI-enabled services.
- भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात, जो वर्तमान में लगभग 250 अरब डॉलर के हैं, उच्च

मूल्य वाले AI-सक्षम सेवाओं की ओर संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

Ques: By which year does the Government aim to provide insurance coverage for all, as stated by Nirmala Sitharaman?

प्रश्न: निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार सभी को बीमा कवरेज किस वर्ष तक प्रदान करने का लक्ष्य रखती है?

- A) 2028
- B) 2029
- C) 2031
- D) 2033
- E) 2040

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Government aims to provide insurance coverage for all by 2033.
- सरकार 2033 तक सभी को बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- A rural outreach plan will cover 25,000 Gram Panchayats as basic units under Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norms.
- एक ग्रामीण योजना के तहत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के मानकों के अनुसार 25,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।
- India's insurance penetration is low, with per capita premium at \$97 compared to the global average of \$943.
- भारत में बीमा पहुंच कम है, जहां प्रति व्यक्ति प्रीमियम \$97 है, जबकि वैश्विक औसत \$943 है।
- The health insurance sector is growing rapidly, reaching ₹1,17,505 crore and covering about 58 crore lives.
- स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जो ₹1,17,505 करोड़ तक पहुंच गया है और लगभग 58 करोड़ लोगों को कवर कर रहा है।

Ques: What is the total investment under the 'Punjab Sikhya Kranti 2.0' initiative?

प्रश्न: 'Punjab Sikhya Kranti 2.0' पहल के तहत कुल निवेश कितना है?

- A) ₹2,000 crore / ₹2,000 करोड़
- B) ₹2,500 crore / ₹2,500 करोड़
- C) ₹3,000 crore / ₹3,000 करोड़
- D) ₹3,500 crore / ₹3,500 करोड़
- E) ₹4,000 crore / ₹4,000 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Government of Punjab, in collaboration with the World Bank, launched 'Punjab Sikhya Kranti 2.0'.
- पंजाब सरकार ने World Bank के साथ मिलकर 'Punjab Sikhya Kranti 2.0' शुरू किया।
- The initiative has a total investment of ₹3,500 crore over a period of 6 years.
- इस पहल के तहत 6 वर्षों में ₹3,500 करोड़ का कुल निवेश किया जाएगा।
- Out of this, the World Bank will provide ₹2,500 crore as loan assistance. The Punjab Government will contribute ₹1,000 crore.
- इसमें से World Bank ₹2,500 करोड़ का ऋण सहायता प्रदान करेगा। पंजाब सरकार ₹1,000 करोड़ का योगदान देगी।
- The initiative aims to strengthen the education system through reforms in its second phase.
- इस पहल का उद्देश्य दूसरे चरण में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना है।

About World Bank :

- Established : 1944
- HQ : Washington DC

- Members : 189
- President : Ajay Banga

Ques: Under SEBI's proposed revised nomination rules, what is the maximum number of nominees allowed for demat accounts and mutual fund folios?

प्रश्न: SEBI के प्रस्तावित संशोधित नामांकन नियमों के तहत डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम कितने नामांकित व्यक्ति (nominees) की अनुमति होगी?

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 7
- E) 10

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has proposed changes to simplify nomination rules for demat accounts and mutual fund folios.
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के नामांकन नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- The number of nominees will be capped at four, replacing the earlier proposal of up to ten nominees.
- नामांकित व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 4 कर दी गई है, जो पहले प्रस्तावित 10 से कम है।
- The proposal allows nominees to operate accounts in case the investor becomes incapacitated but still has contractual capacity.
- प्रस्ताव के अनुसार, यदि निवेशक अक्षम हो जाता है लेकिन अनुबंध करने की क्षमता रखता है, तो नामांकित व्यक्ति खाते का संचालन कर सकते हैं।
- The existing Power of Attorney mechanism can also be used in such situations.

- ऐसी स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग भी किया जा सकता है।
- Only name and relationship of nominee will be mandatory; other details are optional to reduce compliance burden.
- नामांकित व्यक्ति का नाम और संबंध अनिवार्य होगा, जबकि अन्य विवरण वैकल्पिक होंगे।
- Nomination will be the default option for new accounts, and investors must opt out if they do not wish to appoint a nominee.
- नए खातों के लिए नामांकन डिफॉल्ट विकल्प होगा और यदि निवेशक नामांकित नहीं करना चाहते तो उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर होना होगा।
- Existing account holders without nomination will receive reminders via email and SMS.
- जिन मौजूदा खातों में नामांकन नहीं है, उन्हें ईमेल और SMS के माध्यम से याद दिलाया जाएगा।

About SEBI :

- Established : April 12, 1988
- ACT : Securities and Exchange Board of India Act, 1992
- HQ : Mumbai
- Chairman : Tuhin Kanta Pandey

EXAM
Genius

Ques: What is the revised minimum investment limit for Social Impact Funds (SIFs) as per Securities and Exchange Board of India?

प्रश्न: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार सोशल इम्पैक्ट फंड्स (SIFs) के लिए संशोधित न्यूनतम निवेश सीमा क्या है?

- A) ₹10,000
- B) ₹50,000
- C) ₹1,000
- D) ₹2 lakh
- E) ₹5,000

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India has reduced the minimum investment limit in Social Impact Funds (SIFs) from ₹2 lakh to ₹1,000.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल इम्पैक्ट फंड्स (SIFs) में न्यूनतम निवेश सीमा ₹2 लाख से घटाकर ₹1,000 कर दी है।
- SIFs are a sub-category of Alternative Investment Funds (AIFs).
- SIFs, Alternative Investment Funds (AIFs) की एक उप-श्रेणी हैं।
- The move aims to increase participation of retail and small investors in social investing.
- इस कदम का उद्देश्य रिटेल और छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है।
- It aligns SIF investment norms with Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) instruments on the Social Stock Exchange (SSE).
- यह बदलाव Social Stock Exchange (SSE) पर सूचीबद्ध Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) साधनों के अनुरूप है।
- The reform will help improve funding access for social enterprises working in sectors like education, healthcare, and livelihood.
- यह सुधार शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक उद्यमों के लिए फंडिंग बढ़ाने में मदद करेगा।

Static Facts | स्थिर तथ्य:

- SEBI Established: 1988
- SEBI की स्थापना: 1988
- SEBI Act: 1992
- SEBI अधिनियम: 1992
- Headquarters: Mumbai
- मुख्यालय: मुंबई
- Chairman: Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष: तुहिन कांत पांडे

Ques: Which bank became the first in India to launch an overdraft (OD) facility on UPI for women SHG members with PMJDY accounts?

प्रश्न: किस बैंक ने PMJDY खाताधारक महिला SHG सदस्यों के लिए UPI पर ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda launched an overdraft (OD) facility on UPI for verified women Self-Help Group (SHG) members holding Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने सत्यापित महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों पर UPI के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की।
- With this, BoB became the first bank in India to introduce such a digital credit solution.
- इसके साथ ही BoB इस प्रकार की डिजिटल क्रेडिट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया।
- Eligible women can access up to ₹5,000 as overdraft through this facility.
- पात्र महिलाएं इस सुविधा के तहत ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट राशि प्राप्त कर सकती हैं।
- The initiative aims to strengthen financial inclusion and promote women-led economic empowerment.
- इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को मजबूत करना और महिला-नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

- The project was launched by Shivraj Singh Chouhan at the 25th Central Level Coordination Committee meeting on rural development in Hyderabad.
- इस परियोजना का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान द्वारा हैदराबाद में आयोजित ग्रामीण विकास की 25वीं केंद्रीय स्तर समन्वय समिति बैठक में किया गया।

Ques: SEBI has partnered with which company to introduce verified badges for trading apps?

प्रश्न: ट्रेडिंग ऐप्स के लिए वेरिफाइड बैज शुरू करने हेतु सेबी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- B) Amazon / अमेज़न
- C) Google / गूगल
- D) Meta / मेटा
- E) Apple / एप्पल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Securities and Exchange Board of India has partnered with Google to tackle fraudulent trading apps.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स से निपटने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है।
- A “Verified Tick Mark Badge” will be introduced for legitimate stock trading apps.
- वैध ट्रेडिंग ऐप्स के लिए “वेरिफाइड टिक मार्क बैज” शुरू किया जाएगा।
- The badge will appear on apps of registered stockbrokers/intermediaries on the Play Store.
- यह बैज प्ले स्टोर पर पंजीकृत स्टॉकब्रोकर/इंटरमीडियरीज के ऐप्स पर दिखाई देगा।

- The initiative aims to protect investors from fraud and scam apps.
 - इसका उद्देश्य निवेशकों को फर्जी और धोखाधड़ी वाले ऐप्स से बचाना है।
 - Google will use AI technology to identify and remove rule-violating apps and influencers.
 - गूगल AI तकनीक का उपयोग करके नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐप्स और इन्फ्लुएंसर्स को हटाएगा।
-

Ques: Paisalo Digital Limited has recently been appointed as a Business Correspondent (BC) partner for which bank?

प्रश्न: Paisalo Digital Limited को हाल ही में किस बैंक के लिए बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट (BC) पार्टनर नियुक्त किया गया है?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Paisalo Digital Limited has been appointed as a Business Correspondent (BC) partner for Indian Overseas Bank.
- Paisalo Digital Limited को Indian Overseas Bank के लिए बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट (BC) पार्टनर नियुक्त किया गया है।
- This move expands its Banking-as-a-Service (BaaS) platform.
- इस कदम से इसके बैंकिंग-एज-ए-सर्विस (BaaS) प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ है।
- Paisalo Digital already partners with State Bank of India and Bank of India.
- Paisalo Digital पहले से ही State Bank of India और Bank of India के साथ साझेदारी

में है।

- A Business Correspondent (BC) is an agent appointed by banks to provide basic banking services in areas where bank branches are not easily available.
- बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट (BC) वह एजेंट होता है जिसे बैंक उन क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त करते हैं जहां बैंक शाखाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं।

About Indian Overseas Bank (IOB):

- Founded – 1937
- स्थापना – 1937
- Headquarters – Chennai, Tamil Nadu
- मुख्यालय – चेन्नई, तमिलनाडु
- It is a public sector bank.
- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

About Business Correspondent (BC) Model:

- Introduced by the Reserve Bank of India in 2006.
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2006 में शुरू किया गया था।
- Aim – To promote financial inclusion in rural and remote areas.
- उद्देश्य – ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

Ques: The Gruh Sugam Portal has been launched by which organization?

प्रश्न: Gruh Sugam पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?

- A) RBI / RBI
- B) NHB / NHB
- C) NABARD / NABARD
- D) SEBI / SEBI
- E) SIDBI / SIDBI

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- National Housing Bank (NHB) has launched the Gruh Sugam Portal to promote a cost-effective housing finance system.
- नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने Gruh Sugam पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सस्ती हाउसिंग फाइनेंस प्रणाली को बढ़ावा देना है।
- The portal enables defence and government personnel to easily avail home loans from their place of posting.
- यह पोर्टल रक्षा और सरकारी कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग स्थान से आसानी से होम लोन लेने की सुविधा देता है।
- NHB acts as the apex housing finance institution in India, strengthening the housing credit system.
- NHB भारत में शीर्ष हाउसिंग फाइनेंस संस्था के रूप में कार्य करता है और आवास ऋण प्रणाली को मजबूत बनाता है।
- Established → 1988 | Headquarters → New Delhi
- स्थापना → 1988 | मुख्यालय → नई दिल्ली
- The Gruh Sugam Portal simplifies the home loan process and improves accessibility for government and defence employees.
- Gruh Sugam पोर्टल होम लोन प्रक्रिया को सरल बनाता है और सरकारी व रक्षा कर्मचारियों के लिए पहुंच को बेहतर करता है।

Ques: The Government of India has decided to retain the retail inflation target framework for the period 2026–2031 at what level?

प्रश्न: भारत सरकार ने 2026–2031 की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य किस स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया है?

- A) 4%
- B) 5%
- C) 6%
- D) 7%
- E) 8%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Finance has announced that India's inflation target framework will remain unchanged for another five years (2026–2031).
- वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचा अगले 5 वर्षों (2026–2031) तक अपरिवर्तित रहेगा।
- The target inflation is set at 4% with a tolerance band of 2%–6%.
- मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसमें 2%–6% की सहनशीलता सीमा है।
- This is the third consecutive 5-year term of the same framework.
- यह इसी ढांचे का लगातार तीसरा 5-वर्षीय कार्यकाल है।
- As per Section 45ZA of the Reserve Bank of India Act, 1934, the government sets the inflation target every 5 years in consultation with the Reserve Bank of India.
- Reserve Bank of India Act, 1934 की धारा 45ZA के अनुसार, सरकार Reserve Bank of India के परामर्श से हर 5 वर्ष में मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है।
- The framework was first introduced on 5 August 2016.
- यह ढांचा पहली बार 5 अगस्त 2016 को लागू किया गया था।
- First term: 2016–2021; Second term: 2021–2026; Third term: 2026–2031.
- पहला कार्यकाल: 2016–2021; दूसरा: 2021–2026; तीसरा: 2026–2031।
- The Consumer Price Index (CPI) is now based on a new series with base year 2024.
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अब 2024 को आधार वर्ष मानकर नई श्रृंखला पर आधारित है।

Ques: What was the total health insurance premium collected in India in FY25?

प्रश्न: FY25 में भारत में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितना था?

A) ₹80,000 crore / ₹80,000 करोड़

- B) ₹1 lakh crore / ₹1 लाख करोड़
C) ₹1.2 lakh crore+ / ₹1.2 लाख करोड़+
D) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़
E) ₹50,000 crore / ₹50,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India's health insurance sector recorded around 9% growth in FY25.
- भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र ने FY25 में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की।
- Total premium collections exceeded ₹1.2 lakh crore.
- कुल प्रीमियम संग्रह ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक रहा।
- Growth was driven by rising awareness, higher coverage, and increasing healthcare demand.
- वृद्धि का कारण जागरूकता, बेहतर कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग है।
- Insurance Regulatory and Development Authority of India introduced timelines for cashless claims (1 hour pre-authorization, 3 hours final approval).
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कैशलेस क्लेम के लिए समय सीमा तय की (1 घंटा प्री-अप्रूवल, 3 घंटे अंतिम स्वीकृति)।
- Over 1.37 lakh grievances were reported, with 93% resolved in FY25.
- FY25 में 1.37 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 93% का निपटारा किया गया।
- Claim rejections mainly occurred due to policy conditions such as co-pay, sub-limits, and room rent caps.
- क्लेम अस्वीकृति मुख्यतः को-पे, सब-लिमिट और रूम रेंट कैप जैसी शर्तों के कारण होती हैं।
- India's health insurance sector showed strong growth with improved regulations and faster claim processing timelines.
- भारत का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र बेहतर नियमों और तेज क्लेम प्रोसेसिंग के साथ मजबूत वृद्धि दर्शाता है।